भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-68
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में पीएम पोषण योजना

†68. **श्री राजू बिष्ट:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों और छात्रों की संख्या कितनी है;
(ख) वर्ष 2019 से इन जिलों में योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय को इन जिलों में भोजन वितरण में अनियमितताओं, गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, या रुकावटों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार की दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में पीएम पोषण के तहत पोषण घटकों या अवसंरचनात्मक सहायता (जैसे रसोई और भंडारण सुविधाओं) के विस्तार की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के लिए बजट आवंटन 12,500 करोड़ रुपये है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 8,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय और पूरक पोषण वस्तुओं के लिए अतिरिक्त धनराशि शामिल है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है, जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना के लिए कुल आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पीएम पोषण योजना के तहत कवर किए गए स्कूलों और छात्रों की संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के लिए कुल निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -II** में दिया गया है।

(ग) और (घ)**:** पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पंचबती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दार्जिलिंग में श्री राजू बिस्ता, माननीय संसद सदस्य से आवंटित राशि से कम खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कार्यकारी निदेशक गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन ने इसकी जांच की। खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए परिवहन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उनका उत्तर प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी द्वारा परिवहन एजेंसी के अनुबंध को समाप्त कर दिया गया था।

(ङ): इस योजना के दिशा-निर्देशों में रसोई और भंडारण (केसीएस) के निर्माण और मरम्मत का प्रावधान है। रसोई और भंडारण के निर्माण और मरम्मत के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। दार्जिलिंग जिले में 1072 केसीएस और कलिम्पोंग जिले में 358 केसीएस का निर्माण किया गया था**।** पश्चिम बंगाल सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 13,129 रसोई और भंडारण (केसीएस) की मरम्मत और रसोई उपकरणों की 42171 इकाइयों की खरीद को मंजूरी दी गई थी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सी घटक के रूप में कुल आवर्ती बजट के 5 प्रतिशत का प्रावधान है। इसका उपयोग स्कूल पोषण उद्यानों की स्थापना और पहचान किए गए जिलों में पूरक पोषण सामग्री के प्रावधान के लिए किया जा सकता है। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंडा, दूध, चिक्की, ताजे फल, चिकन, रागी माल्ट आदि जैसे अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री भी प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वह दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित सभी छात्रों को अंडे और फलों जैसे पूरक पोषण के लिए फ्लेक्सी-फंड प्रदान करती है।

*****

अनुलग्नक-I

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में पीएम पोषण योजना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम पोषण योजना के तहत शामिल स्कूल और छात्र

जिला	कुल स्कूल	कुल छात्र
दार्जिलिंग	1017	20382
कलिम्पोंग	463	15056

<u>अनुलग्नक -II</u>

'दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में पीएम पोषण योजना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कुल निधियों का वर्षवार विवरण

वर्ष	दार्जिलिंग (रु. लाख में)			कलिम्पोंग (रु. लाख में)		
	अनुमोदित	**नियुक्ति**	**उपयोगिता**	अनुमोदित	**नियुक्ति**	**उपयोगिता**
2019-20	782.54	882.33	755.42	453.99	453.07	409.07
2020-21	797.84	782.48	755.36	482.48	389.38	466.08
2021-22	819.08	726.57	793.49	471.25	417.47	464.37
2022-23	755.84	907.42	852.84	494.10	536.30	512.95
2023-24	807.11	840.36	615.95	521.77	547.20	380.97
2024-25	706.40	790.40	682.94	452.41	497.76	417.95

******